

Fourteenth Lok Sabha**Session : 10****Date : 28-04-2007****Participants : [Rawat Prof. Rasa Singh](#)**

an>

Title: Need to maintain Status Quo in the funding pattern of Centre-State ratio for Sarva Shiksha Abhiyan Scheme.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। वर्ष 2001 में जब केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार थी तो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिये उसका सार्वजनिकीकरण करने के लिये, सर्वजन सुलभ प्राथमिक शिक्षा के लिये एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। उसके अंदर यह निश्चय किया गया था और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2010 तक सारे हिन्दुस्तान के अंदर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के जितने बच्चे हैं, उन्हें प्राथमिक या उच्च शिक्षा प्रदान करने की सारी सुविधायें प्रदान की जायेगी। इस कार्यक्रम को सब स्कूलों में ले जाया जायेगा। स्कूलों में भवन और कमरे बन जायेंगे और जो भी समस्याएँ वहाँ हैं, जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि, वे तैयार हो जायेंगे। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान यू.पी.ए. सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत 329 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है। श्री चिदम्बरम साहब यहाँ बैठे हुये हैं। उन्हें मालूम है कि जहाँ विगत वर्ष इस कार्यक्रम के लिये 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था, इस बार यह 10 हजार 671 करोड़ रुपये है। राज्यों के लिये इस आबंटन में कमी कर दी गई है। एन.डी.ए. सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों के लिये 85:15 का अनुपात रखा था...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : हम क्या करेंगे, हमारी क्या पॉवर है?

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: There should not be any repetition.

... (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 75 प्रतिशत राशि केन्द्र और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा देने के लिये कहा गया और इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में वह राशि 50:50 के अनुपात में कर दी गई है कि 50 प्रतिशत राशि केन्द्र देगी और 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी। अध्यक्ष महोदय, यह संवैधानिक मान्यता है कि राज्यों के पास पैसा नहीं है। अभी 11-12 अप्रैल को दिल्ली में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 75:25 के अनुपात से राज्यों को धनराशि आबंटित करने के लिये केन्द्र सरकार से मांग की गई...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I cannot allow any repetition.

प्रो. रासा सिंह रावत : अगर इसी साल का 50:50 का अनुपात रह गया तो सारे किये-कराये पर पानी फिर जायेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करूँगा कि सर्व शिक्षा अभियान जैसे शैक्षिक कार्यक्रम के लिये राज्यों की मांग के अनुसार और देश की चिन्ता को अनुभव करते हुये 75:25 अनुपात की राशि दी जाये...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please conclude.

प्रो. रासा सिंह रावत :अध्यक्ष महोदय, यह 75:25 अनुपात में राशि आबंटित की जाये।